महत्वपूर्ण एवं खास

एकलाख के इनामी सहित 11 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सली शहीदी सप्ताह के दौरान किरन्दुल थाने में 01 लाख के इनामी सहित 11 नक्सलियों में डीकेएमएस अध्यक्ष कु.रामबती बारसे सहित आयतू मिडियामी, मासा उर्फ देवा मुड़ामी, सुकराम मिडियामी, हुंगा मुरारी, मंगू मंडावी, रामलाल हेमला, केएएमएस सदस्य कु.बुधरी मिडियामी, कु.पायके मिडियामी एवं चैतू मंडावी ने लोनवर्राटू अभियान के तहत एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। गौरतलब है कि विगत 11 महीने से जिले के विभिन्न ग्रामों के नक्सली संगठन में सक्रिय सदस्यों की घर वापसी हेतु थाना व कैंपों और ग्राम पंचायतों में संबंधित क्षेत्र के सक्रिय नक्सलियों के नाम चस्पा कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है तथा एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव द्वारा नक्सल संगठन में सक्रिय नक्सलियों से आत्म समर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। आत्मसमर्पण के दौरान एसपी डॉ. पल्लव के साथ ही एएसपी राजेन्द्र जायसवाल, एसडीओपी किरन्दुल देवांश राठौर, निरीक्षक डीके बरवा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मौसम विभाग की चेतावनी : प्रदेश के कुछ स्थानों हो सकती है भारी बारिश

रायपुर (आरएनएस)। लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण प्रदेश का जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दाब का क्षेत्र तटीय बांग्लादेश और उससे लगे पश्चिम बंगाल के ऊपर स्थित है, इसके साथ ऊपरी वायु का चक्रीय चक्रवाती घेरा 5.8 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार की ओर अगले 48 घंटे में गमन संभावित है। मानसून द्रोणिका फिरोजपुर, रोहतक, अलीगढ़, प्रयागराज, डाल्टनगंज और उसके बाद पूर्व-दक्षिण-पूर्व की ओर निम्न दाब के केंद्र तक 0.9 द्यद्ब ऊंचाई तक विस्तारित है। एक ऊपरी हवा चक्रवाती घेरा पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर 1.5 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने तथा एक-दो स्थानों पर अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः मध्य छत्तीसगढ़ अति से चरम भारी वर्षा का क्षेत्र सरगुजा संभाग के उत्तरी भाग रहने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।

तेंदुए खाल की तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। माना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तेंदुए खाल की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तेंदुआ की खाल और बाइक को जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वीआईपी रोड ग्राम टेमरी के पास बाइक सवार दो व्यक्ति अवैध रूप से वन्य प्राणी तेंदुआ की खाल लेकर उसे बेचने ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस के टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम तेलीबांधा निवासी निखिल कुमार और सरसींवा बलौदाबाजार निवासी मनीष कुमार बताया है। वहीं आरोपियों ने बताया कि मुख्य आरोपी कोरिया निवासी मनोज कुमार कुशवाहा से खाल खरीदे है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण की धारा 09, 39(ख), 49 (ब), 51 और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 03 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को जाचं में लिया है।

चारागाहों में नेपियर घास लगाने का कार्य जल्द करें पूरा-कलेक्टर भीम सिंह

» चारागाह विकास पर पशुधन विकास विभाग की हुई समीक्षा बैठक

रायगढ़, 29 जुलाई 2021/ कलेक्टर भीम सिंह ने चारागाह विकास के संबंध में पशुधन विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक आज नगर निगम के न्यू ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट में ली। उन्होंने कहा कि गौठानों के चारागाह में अधिक से अधिक नेपियर लगवाया जाए। जहां भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वहां शत-प्रतिशत नेपियर लगाए। आगामी दिनों में अतिरिक्त रूट्स उपलब्ध हो जायेंगे उन्हें चारागाह में लगाया जाए। यह शासन की महत्वपूर्ण योजना है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर सिंह ने बैठक में विकासखण्डवार गौठान एवं चारागाह पर विस्तृत चर्चा की। विकासखण्डों में नेपियर की कम रकबे में प्लांटेशन से नाराजगी जताते हुये आगामी दिनों में पर्याप्त रूट्स खरीदी कर चारागाह में लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जहां फेसिंग व सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वहां शत-प्रतिशत नेपियर लगाने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर सिंह ने कहा कि जब तक एक चारागाह में प्लांटेशन कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक दूसरे चारागाह में कार्य प्रारंभ ना किया जाए। उन्होंने चारागाह विकास के लिए विकासखण्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। जिस पर उस विकासखण्ड में चारागाह विकास की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी विभागों को एनजीजीबी के साथ मिलकर कार्य करने को कहा।

बैठक के दौरान उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र के स्टॉफ को विकासखण्ड स्तर में जाकर गौठान समितियों को ट्रेनिंग देने के लिए कहा। इसी तरह कलेक्टर सिंह ने सारंगढ़, घरघोड़ा, बरमकेला, तमनार, धरमजयगढ़, खरसिया, लैलूंगा, रायगढ़, पुसौर आदि ब्लाक में चारागाह की चर्चा करते हुए पुसौर एवं रायगढ़ में चारागाह में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सीईओ की सराहना की। जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल ने कहा कि गोठान समिति, पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सीईओ सभी अपनी सामंजस्य बनाकर कार्य करें। कलेक्टर सिंह ने गोठानों में पशुओं की उपस्थिति की जानकारी लेते हुये बरमकेला एवं रायगढ़ में पशुओं की कम उपस्थिति पर गौठानों में पशुओं को बढ़ाने के साथ चरवाहे को नियमित रूप से राशि देने के निर्देश दिए। सभी सीईओ को निर्देशित किया कि चारागाह में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करें। समिति द्वारा चारागाह में खिलाये जा रहे चारे एवं विक्रय का रिकार्ड रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने वर्तमान में लगभग 121 एकड़ रिक्त स्थानों में अगले एक सप्ताह में नेपियर रूट्स उपलब्ध कराने के साथ विभाग को लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने रूट्स लगाने के कार्य को जल्द खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने चारागाहों के लिए चिन्हांकित भूमि पर अतिक्रमण हो तो उसे तत्काल हटाने के निर्देश सभी एसडीएम को दिए। उन्होंने कहा कि जिले में जितने सक्रिय गौठान है उतने चारागाह विकसित करने है।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ.रवि मित्तल, उप संचालक पशुपालन डॉ.आर.एच.पाण्डेय, सभी विकासखण्डों के जनपद सीईओ, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के कर्मचारी एवं केवीके कर्मचारी उपस्थित थे।

मल्दा के समीप क्षतिग्रस्त नाली का होगा पुनर्निर्माण

» पीएमजीएसवाय ने ठेकेदार को जारी किया निर्देश

रायगढ़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-श्री के अंतर्गत विकासखण्ड सारंगढ़ की सड़क कुटेला-कोसीर-सिंघनपुर से मल्दा (अ)के निर्माण कार्य की गुणवत्ता संबंधी खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी। इस संबंध में जानकारी देते हुये ईई पीएमजीएसवाय व्ही.के.मिंज ने बताया कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का समय-समय पर विभागीय अधिकारियों व राज्य गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा जांच की जाती रही है। जिसमें परिक्षण प्रतिवेदन पर गुणवत्ता प्रबंधन पर कार्य किया जा रहा है। ग्राम मल्दा के पास सीसी सड़क के किनारे निर्माणाधीन नाली के दौरान बारिश एवं अर्थ प्रेशर के कारण नाली का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। जिसे संज्ञान में लेकर 24 जुलाई 2021 को ही संबंधित ठेकेदार को नाली के हिस्से को तोड़कर पुनर्निर्माण करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। प्रभावित भाग को तोड़कर दोबारा नाली निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उल्लेखनीय है कि निर्माणाधीन इस सड़क की लंबाई 21.70 कि.मी. है। सड़क की लागत 1152.69 लाख है। जिसे 19 मई 2020 से ठेकेदार मेसर्स आर.के.ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी कोरबा द्वारा बनाया जा रहा है। वर्तमान में उक्त सड़क में 17.00 कि.मी.बीटी एवं 1.50 सीसी कार्य का पूर्ण कर लिया गया है। शेष सड़क में सोल्डर और आवश्यकतानुसार नाली निर्माण का कार्य जारी है।

चारागाहों में जल्द पूरा करें प्लांटेशन- कलेक्टर भीम सिंह

» कोसीर व सहसपानी गौठान के निरीक्षण में पहुंचे कलेक्टर

» लेन्द्रा के मल्टी एक्टिविटी सेंटर का भी लिया जायजा

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने बुधवार को सारंगढ़ ब्लाक के कोसीर के गौठान में चारागाह का निरीक्षण कर वहां पर संचालित की जा रही विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। यहां उन्होंने कहा कि चारागाह में महिलाओं की अधिक से अधिक एक्टिविटी में सहभागिता सुनिश्चित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करें ताकि इसे आदर्श चारागाह और मल्टी एक्टिविटी के रूप में स्थापित किया जा सके। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल भी उपस्थित रहे।

श्री सिंह ने कोसीर चारागाह में संचालित विभिन्न गतिविधियों में नेपियर लगाना, मुर्गीपालन, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, सब्जी, मछली पालन एवं रागी फसल का निरीक्षण किया। गौठान में विविध आजीविका मूलक गतिविधियों के संचालन के लिए उन्होंने कार्यरत समूह की तारीफ की। इन सभी जगह जाने के लिए एक मार्ग निर्माण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर सिंह ने गौठान में नेपियर रूट्स कम प्लांटेशन व पहले से लगे नेपियर की कटाई न होने को लेकर नाराजगी जताते हुए जल्द कटाई करने तथा अन्य रिक्त स्थानों पर नेपियर घास लगाने के सख्त निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने सहसपानी फारेस्ट गोठान के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सिंह ने चारागाह, खाद निर्माण एवं पानी की व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां चारागाह निर्माण की भी जानकारी ली। उन्होंने गौठान के समीप रिक्त स्थानों में पशुओं के लिए नेपियर घास का प्लांटेशन करने के निर्देश वन विभाग के अधिकारी को दिए। इसके साथ ही उन्होंने गौठान में वर्मी कम्पोस्ट के लिए पिट तथा अन्य निर्माण कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सभी कार्य पूर्ण किए जा चुके है। उन्होंने गौठान में गेट लगाने तथा पानी की व्यवस्था का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

छात्रावास/ आश्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु निजी प्रेक्टिशनरों से 10 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़ । जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में वर्ष 2021-22 हेतु प्रवेशित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये स्वस्थ तन-स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा)योजनान्तर्गत रायगढ़ जिले के निजी प्रेक्टिशनरों जिनकी योग्यता एम.बी.बी.एस., बी.ए.एम.एस. एवं बी.एच.एम.एस.डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक संस्थाओं (छात्रावास/आश्रम)के लिए 10 अगस्त 2021 तक आवेदन अत्र आमंत्रित किए गए है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी अनुसार निजी प्रेक्टिशनरों चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास/आश्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 750 रुपये प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास/आश्रमों में छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 1200 रुपये प्रतिभ्रमण मानदेय भुगतान दिया जाएगा। निजी चिकित्सक माह में कम से कम दो बार छात्रावास/आश्रम के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज करेंगे।

इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पेड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज, संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, स्थाई/अस्थाई मोबाइल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक के खाता के प्रथम पृष्ठ (जहां फोटो चस्पा हो)की छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से भेज सकते है। आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में नहीं लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किये जायेंगे। निजी चिकित्सकों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा। चिकित्सकीय कार्य हेतु अनुबंध के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, रायगढ़ में संपर्क कर सकते है।

महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित पेंशन योजना का मामला उठा

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज प्रदेश में बाल विकास विभाग की संचालित पेंशन योजना का मामला उठा।

विधायक डमरूधर पुजारी ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाते हुए मंत्री से पूछा कि प्रदेश में विभाग की कौन-कौन से पेंशन योजनाएं चल रही है। इसके जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने बताया कि प्रदेश में सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाएं एवं प्रतिमा दी जा रही पेंशन राशि की जानकारी केन्द्रांश व राज्यांश सहित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद सहारा योजना एवं मुख्यमंत्री पेंशन योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं की पेंशन राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अन्य एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं के अंतर्गत 38184 हितग्राही है व माह जून 2021 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है।

कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1.19 करोड़ टीके लगाए गए

» 96.25 लाख लोगों ने पहला टीका और 22.54 लाख लोगों ने लगवाए हैं दोनों टीके

» 45 वर्ष से अधिक के 87 प्रतिशत और 18 से 44 आयु वर्ग के 29 प्रतिशत नागरिक लगवा चुके हैं पहला टीका

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक (28 जुलाई तक) एक करोड़ 18 लाख 78 हजार 431 टीके लगाए गए हैं। प्रदेश के 96 लाख 24 हजार 588 लोगों को इसका पहला टीका और 22 लाख 53 हजार 843 को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में तीन लाख नौ हजार 203 स्वास्थ्य कर्मियों, तीन लाख 17 हजार 010 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 50 लाख 91 हजार 753 और 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 39 लाख छह हजार 622 नागरिकों को कोरोना से बचाव का पहला टीका लगाया जा चुका है। वहीं दो लाख 44 हजार 653 स्वास्थ्य कर्मियों, दो लाख 26 हजार 034 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 16 लाख 52 हजार 878 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के एक लाख 30 हजार 278 लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं।

प्रदेश में 91 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों, 96 शत-प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 87 प्रतिशत नागरिकों और 18 से 44 आयु वर्ग के 29 प्रतिशत युवाओं ने कोरोना से बचाव का पहला टीका लगवा लिया है। वहीं 72 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों, 77 प्रतिशत फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 वर्ष से अधिक के 28 प्रतिशत लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। प्रदेश में कुल एक करोड़ 99 लाख 32 हजार 392 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य है। इनमें तीन लाख 39 हजार 732 स्वास्थ्य कर्मी, दो लाख 93 हजार 040 फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 58 लाख 66 हजार 599 तथा 18 से 44 आयु वर्ग के एक करोड़ 34 लाख 33 हजार 021 नागरिक शामिल हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं० 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं सीनियर एडवाईजर श्री तरुणजीत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं शासन व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य क्षय में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को इसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का अनुपूरक बजट पारित

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण अंचल के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रूपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की। यह योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में 2485.59 करोड़ रूपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों को प्रदेश है, किसान हमारे अन्नदाता है। इस अनुपूरक बजट की संरचना को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि हमने अपनी न्याय की अवधारणा को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 60 लाख मीटरिक टन चावल लेने की सहमति दी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ से मात्र 24 लाख मीटरिक टन चावल लिया है। इसके कारण अतिशेष धान की नीलामी हमें घाटा उठाकर करनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद भी हम हर हाल में किसानों की मदद कर रहे है, इसके लिए हमें भले ही कर्ज लेना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लेकर राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना तक, अभी वक्त तो बहुत कम गुजरा है, लेकिन इसके लाभ का दायरा लाखों लोगों तक पहुंच गया है। किसानों की ऋण माफी, सिंचाई कर माफी, समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने वाले किसानों को देश में सबसे ज्यादा लाभ, वनोपज की खरीदी से आदिवासी और वन आश्रित परिवारों को सर्वाधिक लाभ, गोधन न्याय योजना जैसे हमारे नवाचारों के आंकड़े अब अरबों में पहुंच चुके हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक, छोटे-छोटे गांवों, कस्बों, गली, मोहल्लों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का हमारा छत्तीसगढ़ी मॉडल की देश में है, तो इस पर भी अगर अभिमान न करें तो क्या करें? उन्होंने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ी मॉडल ने सिर्फ छत्तीसगढ़ निवासियों को ही नहीं, बल्कि हमारे जैसी परिस्थितियों में देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों के जीवन में भी उम्मीद की नई किरण जगाई है। यही कारण है कि मलेरिया मुक्त बस्तर हो, मनरेगा हो, वनोपज की खरीदी हो, कृषि उपज की खरीदी हो, नरवा, गरूवा, घुरुवा, बाड़ी हो या गोधन न्याय योजना जैसे ग्राम और वन उन्मुख नवाचार, कुपोषण के विरुद्ध मुहिम हो, मलेरिया का उन्मूलन हो, हमारी ऐसी हर पहल आज देश में उन लोगों के लिए आशा लेकर आई है, जिन्हें बरसों से ऐसे सकारात्मक बदलाव की जरूरत थी।